

गीजगंदा सोमैया

बनाम

कर्नाटक राज्य

12 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायाधिपति]

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डॉ अरिजीत पासायत, द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले को चुनौत दी गयी है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा सुनाई की गई सजा की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। उक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारत दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और डिफॉल्ट शर्त के साथ 8,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

एक चेंगापा (बाद में 'मृतक'के रूप में संदर्भित), उनकी पत्नी श्रीमती। बेबी चेंगप्पा (पीडब्लू-1), आरोपी और अधिकांश गवाह गारवले गांव के

निवासी हैं। इस बात पर विवाद नहीं है कि आरोपी और मृतक आपस में रिश्तेदार थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार गीजगांडा परिवार, जिससे आरोपी और मृतक संबंधित हैं, के पास लगभग 348 एकड़ जमीन है। उसमें से लगभग 48 एकड़ जमीन दान कर दी गई और बाकी जमीन परिवार के पास थी। उक्त गीजगांडा परिवार में छह हिस्सेदार थे। उक्त छह हिस्सेदारों का शेष क्षेत्र के संबंधित हिस्से पर कब्जा था। मृतक पारिवारिक भूमि में समान बंटवारे और हिस्सेदारी का दावा कर रहा था, जिसका आरोपी ने विरोध किया था और इसके परिणामस्वरूप 23.9.1995 को रात 8.00 बजे मृतक चेंगप्पा की हत्या कर दी गई। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 21.9.1995 को यानी घटना से दो दिन पहले राजस्व निरीक्षक ने मृतक द्वारा किए गए न्यायसंगत बंटवारे के अनुरोध पर पारिवारिक जमीन का दौरा कर निरीक्षण किया था। दिनांक 23.9.1995 को सुबह मृतक अपनी पत्नी पीडब्लू-1 को यह बताकर घर से निकला कि वह राजस्व निरीक्षक से मिलने मदापुरा जा रहा है। उस समय, उन्होंने एक एचएमटी घड़ी, "जीडीसी" लिखी सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन और 2,500/- रुपये की राशि पहनी हुई थी। उसने पीडब्लू-1 को सूचित किया कि वह शाम को वापस आ सकता है और यदि वह नहीं लौटा, तो वह अगले दिन सुबह वापस आएगा। चूंकि मृतक 24.9.1995 की सुबह भी वापस नहीं आया, पीडब्लू-1 काम पर जाने के लिए कॉफी लैंड में गई और रास्ते में ठकेरी-

गरवले रोड पर उसने देखा कि उसके पति का शव, शरीर पर चोटें आई हुई सड़क किनारे पड़ा हुआ था। यह देखकर वह घर वापस गई और घटना की जानकारी अपने बच्चों को दी और परिवार के सभी सदस्य वहां वापस आ गए। तब तक अधूरी सूचना प्राप्त पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पीडब्लू-1 का बयान दर्ज कर उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट मानकर अपीलकर्ता/आरोपी काे मिलाते हुए दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध क्रमांक 215/1995 में मामला दर्ज कर लिया।

4. मामला दर्ज होने के बाद महाजार को पकड़ने, जांच कार्यवाही तैयार करने जैसी अनिवार्य प्रक्रियाएं की गईं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोपियों की तलाश की गई। उसी दिन, यानी 24.9.1995 को, आरोपी नंबर 1 स्वेच्छा से जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया, उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई और उनके स्वैच्छिक बयान से, Ex.P-14 के रूप में चिह्नित अनुमेय भाग, दर्ज किया गया।

स्वैच्छिक बयान के आधार पर, आरोपी नंबर 1 के घर से मृतक की सोने की चेन, अंगूठी और संबंधित अपराध में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार की बरामदगी की गई। उन्हें खून से सने कपड़ों के साथ जब्त कर लिया गया, जिनकी फॉरेंसिक विज्ञान जांच की गई। एफएसएल, शव

परीक्षण, सीरोलॉजिस्ट सहित सभी रिपोर्ट प्राप्त होने और जांच पूरी होने पर, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 भा.द.स. के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

5. आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को परीक्षित करवाया। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि दुश्मनी के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी पाया। हालाँकि, सह-अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया और बरी करने का आदेश दर्ज किया गया।

7. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य इर्द-गिर्द घूमता है, क्योंकि वास्तविक हमले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया वे हैं:

(i) मकसद;

(ii) आखिरी बार एक साथ देखा गया'

(iii) मृतक के सोने के आभूषणों की खोज/बरामदगी और आरोपी नंबर 1 के घर से जब्त किए गए हत्या के हथियार के साथ-साथ आरोपी नंबर 1 के खून से सने कपड़े; और अंत में

(iv) आरोपी नंबर 1 द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव।

8. उच्च न्यायालय ने पाया कि परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए निर्णायक थीं और इसलिए, अपील को खारिज करके दोष सिद्ध और सजा की पुष्टि की गई।

9. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य आरोपी के अपराध को स्थापित नहीं करता है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला स्थापित करने के लिए जिन परिस्थितियों को उजागर किया गया है, वह परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत नहीं करती है। दोषी के किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी दें।

10. दूसरी ओर रेस्पोंडेंट के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

11. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आपत्तिजनक तथ्य और परिस्थितियां आरोपी की बेगुनाही या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाएं। (देखें हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर (1977) एससी 1063, एराडु बनाम हैदराबाद राज्य, एआईआर (1956) एससी 316, ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर (1983) एससी 446, यूपी राज्य बनाम। सुखबासी, एआईआर

(1985) एससी 1224, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1987) एससी 350, और अशोक कुमार चटर्जी बनाम एमपी राज्य, एआईआर (1989) एससी 1890। जिन परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया गया है कि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1954) एससी 621 में यह यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो आरोपी की बेगुनाही को नकारात्मक कर दे और किसी भी उचित संदेह से परे अपराध को साबित कर दे।

हम सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एससीसी 193 में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, स्थापित कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी

चाहिए और। सबूतों की शृंखला में कोई अंतराल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में । एआईआर (1990) एससी 79, यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना होगा:

- (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;
- (2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों;
- (3) परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं; और (4)

दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसके बेगुनाही साथ असंगत होने चाहिए।

यूपी राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) सीआरएल में। एलजे 1104, यह इंगित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह दो निष्कर्षों के लिए उचित रूप से सक्षम है, तो आरोपी के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

12. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक 'विल्स सर्कमस्टैंटियल एविडेंस' (अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम बताए हैं: (1) किसी भी कानूनी अनुमान के आधार के रूप में कथित तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध और उचित संदेह से परे साबित होने चाहिए, (2) सबूत का भार



हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, (3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है; (4) अपराध के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषी तथ्यों को अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत होना चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए; और (5) यदि अभियुक्त के अपराध पर कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने का अधिकार रखता है।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसे 1952 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एमपी राज्य एआईआर (1952) एससी 343 में, यह इस प्रकार देखा गया:

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के

साथ सुसंगत होने चाहिए। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो साबित होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जाए और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1984) एससी 1622 के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटते समय, यह माना गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन में कमी की कमजोरी को झूठे बचाव या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने से पहले, इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और (5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

14. कुछ परिस्थितियाँ जिन्हें उजागर करने की आवश्यकता है, वे हैं मृतक के सोने के आभूषणों के साथ-साथ अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी। अपीलकर्ता के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिये गये। अभियोजन ने बरामदगी के बारे में अपना पक्ष स्थापित करने के लिए पीडब्लू 6 और 12 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। पीडब्लू-6, सुनार जिसे

सोने के आभूषणों का परीक्षण और वजन करने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने स्वीकार किया कि वह आरोपियों से आभूषणों की बरामदगी के लिए पुलिस अधिकारी के साथ गए थे, लेकिन जांच के दौरान दिए गए बयान के कुछ हिस्सों से मुकर गए। पीडब्लू-12 ने विशेष रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने पुलिस और महाज्जार गवाह को सोने की चेन एमओ 10 व आरोपी के खून से सने कपड़े यानी एमओ 14 जैसी वस्तुओं की खोज के लिए नेतृत्व किया। इन्हें कपड़ों के साथ फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। एफएसएल अधिकारी के साक्ष्य और उनकी रिपोर्ट ने समान रूप से स्थापित किया कि खून के धब्बे थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') भी लागू होती है। जैसा कि इस न्यायालय ने जेपी आनंद बनाम डीजी बाफना, एआईआर (2002) एससी 141, और एज़िल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर (2002) एससी 2017 में कहा था, मृतक से संबंधित वस्तुओं के वैध कब्जे के बारे में अभियुक्तों के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, उस समय को ध्यान में रखते हुए, जब हत्या की गई थी और जो शव मिला है और आरोपी के कब्जे से जो सामान बरामद हुआ है, उससे यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि आरोपी के पास न केवल मृतक से संबंधित सामान था, बल्कि उसने मृतक की हत्या भी की थी। मृतक से संबंधित वस्तुएं आरोपी के कब्जे में थी, जिसने स्वेच्छा से खुलासा किया था,

जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत उपधारणा स्पष्ट रूप से लागू होती है।

15. मामले में अभियोजन पक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयान और ऐसे बयानों के परिणामस्वरूप चोरी की संपत्ति, खून से सनी शर्ट और अपराध के हथियार की बरामदगी है। आरोपी व्यक्तियों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों की स्वीकार्यता को दो आधारों पर चुनौती दी गई है, यानी, (i) तथ्यात्मक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था, और (ii) दिया गया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि पुलिस हिरासत में आरोपी व्यक्ति द्वारा कबूल किया गया बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से 26 के पूर्वोक्त नियम में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें प्रावधान है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी भी नए तथ्य की खोज की जाती है। ऐसी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं,

जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, साबित की जा सकती है। धारा 27, धारा 25 और 26 का परन्तुक है। ऐसे बयानों को आम तौर पर प्रकटीकरण बयान कहा जाता है जिससे उन तथ्यों की खोज होती है जो संभवतः निर्माता के विशेष ज्ञान में होते हैं। धारा 27 इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होती है कि यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य वास्तव में खोजा जाता है, तो कुछ गारंटी दी जा सकती है कि जानकारी सत्य थी और तदनुसार इसे साक्ष्य के रूप में दिए जाने की सुरक्षित रूप से अनुमति दी जा सकती है।

चूंकि इस धारा का पुलिस द्वारा अक्सर दुरुपयोग होने का आरोप है, इसलिए अदालतों को इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अदालत को पुलिस द्वारा सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि इस प्रावधान का दुरुपयोग होने का खतरा है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपरोक्त धारा के संदर्भ में दिए गए किसी भी बयान को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिया गया था। अदालत को सावधान रहना होगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदी के एक साधारण मामले को आरोपी के बयान

के आधार पर तथ्य की खोज का मामला बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया हो।

16. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में कानून की स्थिति को पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य में सर जॉन ब्यूमोंट द्वारा विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया था। वी. एम्परर, एआईआर (1947) पीसी 87, जिसमें यह आयोजित किया गया था:

"धारा 27, जिसे कलात्मक शब्दों में नहीं लिखा गया है, पूर्ववर्ती धारा द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद प्रदान करती है, और पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाती है। धारा को संचालन में लाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि की खोज पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप एक तथ्य को पेश किया जाना चाहिए, और उसके बाद इतनी सारी जानकारी जो उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, उसे साबित किया जा सकता है। यह धारा इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य वास्तव में खोजा जाता है, तो कुछ गारंटी दी जा सकती है कि जानकारी सत्य थी, और तदनुसार उसे साक्ष्य

के रूप में सुरक्षित रूप से देने की अनुमति दी जा सकती है; लेकिन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य जानकारी खोजे गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर, जिससे संबंधित ऐसी जानकारी की आवश्यकता होती है, की सीमा पर निर्भर होना चाहिए। आम तौर पर यह धारा तब लागू होती है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति छुपाने के स्थान से कोई वस्तु, जैसे कि शव, हथियार, या आभूषण बरामद करवाता है, जिससे उस अपराध से जुड़ा हुआ कहा जाता है। क्राउन के लिए श्री मेगॉ ने तर्क दिया है कि ऐसे मामले में 'खोजा गया तथ्य उत्पादित भौतिक वस्तु है, और कोई भी जानकारी जो उस वस्तु से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, उसे साबित किया जा सकता है। इस दृष्टि कोण से, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि उत्पादित शव उसके द्वारा मारे गए व्यक्ति का है, कि उत्पादित हथियार वह है जिसका उपयोग उसने हत्या में किया था, या कि उत्पादित आभूषण डकैती में चुराए गए थे, ये सभी होंगे स्वीकार्य होंगे, यदि यह धारा 27 का प्रभाव हो, पुलिस के सामने या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर पिछली दो धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सार बचेगा। वह प्रतिबंध संभवतः



विधानमंडल के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में किसी व्यक्ति को अनुचित दबाव डालकर अपराध कबूल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन यदि प्रतिबंध हटाने के लिए केवल बाद में उत्पादित वस्तु से संबंधित जानकारी को स्वीकारोक्ति में शामिल करना आवश्यक है, तो यह मान लेना उचित लगता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियाँ अवसर के बराबर साबित होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। सामान्य सिद्धांतों पर न्यायालय सोचता है कि धारा 26 के परन्तुक को धारा के सार को रद्द करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय के विचार में अनुभाग के भीतर 'खोजे गए तथ्य'को उत्पादित वस्तु के समकक्ष मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का उत्पादन किया गया है और इसके बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रकट हुई वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी, उस परिप्रेक्ष्य में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि "मैं अपने घर की छत

पर छिपा हुआ चाकू पेश करूंगा"से चाकू की खोज नहीं होती है; चाकू की खोज कई साल पहले की गई थी। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि मुखबिर के घर में उसकी जानकारी के अनुसार एक चाकू छिपाया गया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध के कमीशन में चाकू का इस्तेमाल किया गया था, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में 'जिससे मैंने ए पर वार किया'शब्द जोड़ दिए जाएं तो ये शब्द स्वीकार्य हैं, क्योंकि वह अभियुक्त के घर में रखे चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।"

17. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, एआईआर (1960) एससी 1125 में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 25 और 26 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक बुराई पर प्रहार करना था, अर्थात् दागी लोगों से साक्ष्य प्राप्त करने के खतरे से रक्षा करना। अपराधों के आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में स्रोत। ये धाराएं एक कानून का हिस्सा हैं जो न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य की प्रासंगिकता और तथ्यों के प्रमाण से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करती हैं। राज्य उन अपराधियों को दंडित करने के लिए उतना ही चिंतित है जो अपराध करने के लिए दोषी साबित हो सकते हैं, जितना कि यह उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है

जिन्हें इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। धारा 27 जानकारी को इस आधार पर स्वीकार्य बनाती है कि हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के अनुसार तथ्य की खोज उसके द्वारा दिए गए बयान की सत्यता की गारंटी है और विधायिका ने उस आधार पर नियम का अपवाद बनाने का विकल्प चुना है। ऐसे कथन के प्रमाण पर रोक लगाना। ऐसे तथ्यों की खोज के लिए जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयानों के साक्ष्य को स्वीकार करने का सिद्धांत, जिसका उपयोग उसके खिलाफ साक्ष्य में किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से उचित है। उस मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि उसका बयान जिसमें अपराध के हथियार गंडासा की बरामदगी हुई थी, अस्वीकार्य था। आरोपी देवमन ने गंडासा सौंपने का बयान दिया था, जिसे उसने टैंक में फेंकना बताया था और उसे बरामद करा दिया है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 जिसने कथित तौर पर भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए हिरासत में मौजूद व्यक्तियों और हिरासत से बाहर के व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव पैदा किया है, अप्रवर्तनीय है। पूर्ण पीठ की राय के बाद न्यायालय की एक खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आरोपी द्वारा दिए गए बयान को विचार से बाहर कर दिया

और माना कि घटना के दिन आरोपी द्वारा गंडासा उधार लेने की कहानी अविश्वसनीय थी। आरोपी को बरी कर दिया गया लेकिन यूपी राज्य के कहने पर, उच्च न्यायालय ने इस अदालत में अपील दायर करने का प्रमाण पत्र दिया। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की स्थिति से सहमत नहीं था और उस बयान के आलोक में सबूतों की समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया, जहां तक यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित था कि खोज स्वीकार्य है। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"उच्च न्यायालय का विचार था कि गंडासा को उसके छिपने के स्थान से लाने मात्र से यह स्थापित नहीं होता है कि देवमन स्वयं पे इसे टैंक में रखा था, और वैध रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी और ने इसे टैंक में रखा हो या कि देवमन ने किसी को उस गंडासा को टैंक में रखते हुए देखा था या किसी ने उसे टैंक में पड़े गंडासा के बारे में बताया हो, लेकिन पहले से ही निर्धारित कारणों से देवमन द्वारा दी गई जानकारी साबित करने योग्य है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित है जिससे पता चला है; और उसका यह कथन कि उसने गंडासा टैंक में फेंका

था, वह सूचना है जो स्पष्ट रूप से गंडासा की खोज से संबंधित है। स्वीकारोक्ति के आलोक में मानव रक्त से सने हुए गंडासा को देवमन के कहने पर उसके छिपने के स्थान से खोजा गया उसके द्वारा यह कहना कि उसने इसे उस टैंक में फेंक दिया था जिसमें यह पाया गया था, इसलिए महत्व प्राप्त करता है, और उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों को नष्ट कर देता है।"

मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1976) एससी 483 के मामले में यह माना गया था कि अभिव्यक्ति 'खोजे गए तथ्य'में न केवल उत्पादित भौतिक वस्तु शामिल है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहां से इसे उत्पादित किया गया है और आरोपी का ज्ञान भी शामिल है। धारा के शब्दों की व्याख्या करते हुए "इतनी सारी जानकारी" जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, न्यायालय ने माना कि "विशिष्ट रूप से "शब्द का अर्थ "सीधे", "निस्संदेह", "सख्ती से", "अचूक" है। सिद्ध जानकारी के दायरे को सीमित करने और परिभाषित करने के लिए इस शब्द का सलाहपूर्वक उपयोग किया गया है। वाक्यांश "विशिष्ट रूप से" का संबंध "इस प्रकार खोजे गए तथ्य से है"। यह वाक्यांश अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो किसी तथ्य की खोज का प्रत्यक्ष कारण है। बाकी जानकारी को बाहर करना होगा।

इयरभद्रप्पा उर्फ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, [1983] 2 एससीआर 552 में, यह माना गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए दो शर्तें पूर्व-आवश्यक हैं, अर्थात्, (i) जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो तथ्य की खोज का कारण बने, और (ii) जानकारी खोजे गए तथ्य से 'स्पष्ट रूप से संबंधित'होनी चाहिए। धारा 27 के तहत केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य है जो वास्तव में खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता का निर्णय करते समय, न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ए) से (ओं) के तहत अनुमान की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए, न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व की कल्पना कर सकता है जिसके प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए घटित होने की संभावना है। उस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया उनमें से एक यह थी कि घटना के एक साल बाद गिरफ्तार होने पर, आरोपी ने पुलिस के सामने एक बयान दिया जिससे मृतक के कुछ सोने के गहने व छह रेशम साड़ियाँ, अलग-अलग स्थानों से, बरामद हो गए, जिनकी पहचान गवाह द्वारा मृतक के सामान के रूप में की गई थी। उस संदर्भ में अदालत ने कहा:

"इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता प्रदर्श पी-35 द्वारा दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। धारा 27 के तहत केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य है जो वास्तव में खोजे गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से संबंधित है। 'तथ्य'शब्द का अर्थ कुछ ठोस या भौतिक तथ्य है जिससे जानकारी सीधे तौर पर संबंधित होती है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू, पुत्र गोपीनाथ शिंदे और अन्य, जेटी (2000) 5 एससी 575 में यह माना गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि के सिद्धांत पर आधारित थी और धारा को वास्तविक और विस्तारित कर रही थी। अर्थ, आयोजित:

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार, बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर की गई खोज में कोई तथ्य पाया जाता है, ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। जानकारी प्रकृति में इकबालिया या गैर-प्रेरकात्मक हो सकती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज होती है जो एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। इसलिए विधायिका ने

ऐसी जानकारी का स्वीकार्य भाग को न्यूनतम तक सीमित करके साक्ष्य को उपयोग करने की अनुमति दी। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति किसी तथ्य की खोज नहीं है जैसा कि अनुभाग में परिकल्पित है। पुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट, एआईआर (1947) पीसी 67 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय, इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे उद्धृत प्राधिकारी है कि अनुभाग में परिकल्पित 'खोजे गए तथ्य'में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का प्रस्तुतीकरण किया गया था; इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। "

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अलावा, अदालतें साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टांत (ए) और धारा 106 के तहत अनुमान लगा सकती हैं। गुलाब चंद बनाम एमपी राज्य में। एआईआर (1995) एससी 1598, जहां घटना के तुरंत बाद आरोपी के कब्जे से मृतक के गहने बरामद किए गए थे, इस न्यायालय ने कहा:

"यह सच है कि केवल चोरी के सामान की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चोरी का सामान रखने वाला व्यक्ति हत्या और डकैती के अपराध का दोषी है।



लेकिन उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी होना तथ्यों और परिस्थितियों, मामले की प्रकृति और साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सांवत खान बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1956) एससी 54 में इस न्यायालय द्वारा यह संकेत दिया गया है कि परिस्थितियों से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह भी संकेत दिया गया है कि जहां अभियुक्तों के खिलाफ एकमात्र सबूत चोरी की संपत्तियों की बरामदगी है, तो हालांकि परिस्थितियां यह संकेत दे सकती हैं कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने हत्या की थी। इस न्यायालय द्वारा सावधानी का एक नोट दिया गया है जिसमें संकेत दिया गया है कि संदेह को सबूत की जगह नहीं लेनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इस न्यायालय का उक्त निर्णय पर ध्यान दिया है, परन्तु जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही संकेत दिया है, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय ने

तुलसीराम कानू बनाम राज्य, एआईआर (1954) एससी 1 में दिए गए इस न्यायालय के अन्य निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि धारा 114, चित्रण (ए) के तहत अनुमान लगाने की अनुमति दी गई है। साक्ष्य अधिनियम के 'महत्वपूर्ण समय कारक'के तहत तैयार किया जाना है। यदि हत्या के तुरंत बाद मृतक के पास मौजूद आभूषण किसी व्यक्ति के पास पाए जाते हैं, तो अपराध की उपधारणा की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यदि अंतराल में कई महीने समाप्त हो गए थे, तो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वर्तमान मामले में, यह स्थापित किया गया है कि हत्या के तुरंत अगले दिन, आरोपी गुलाब चंद ने मृतक के कुछ गहने बेच दिए थे और 3-4 दिनों के भीतर उक्त चोरी किए गए सामान की बरामदगी आरोपी की निशानदेही से उसके घर से हाे गयी थी, जिसे इस न्यायालय ने 'महत्वपूर्ण समय कारक'के रूप में इंगित किया है, को वर्तमान मामले का निर्णय करते समय नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यहां यह संकेत दिया जा सकता है कि इयरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,

[1993] 2 एससीसी 330 में इस न्यायालय के बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने माना है कि धारा 114 चित्रण (ए) साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान की प्रकृति साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कब्जा हाल ही में हुआ है या अन्यथा और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अपराध की धारणा को सही ठहराने के लिए हालिया कब्जे की मात्रा कितनी है, यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि चुराई गई वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में आसानी से पारित होने के लिए गणना की जाती है या नहीं। यदि चोरी की गई वस्तुएँ ऐसी थीं जिनके आसानी से हाथ से जाने की संभावना नहीं थी, तो बीतने वाली एक वर्ष की अवधि को बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब अपीलकर्ता उस अवधि के दौरान फरार हो गया हो। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा यह सही माना गया है कि अभियुक्त इतना समृद्ध नहीं था कि वह उक्त आभूषणों को अपने पास रख सके। इस मामले में पेश किए गए सबूतों की प्रकृति और उसके कब्जे से उक्त वस्तुओं की

बरामदगी और हत्या और डकैती के तुरंत बाद मृतक के आभूषणों का आरोपी द्वारा लेन-देन अपीलकर्ता के खिलाफ उक्त अपराध के घटित होने का उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस दावे को छोड़कर कि गहने आरोपी के परिवार के थे, जिसका दावा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है, हत्या के तुरंत बाद उक्त आभूषणों के वैध कब्जे के लिए आरोपी द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस मामले के तथ्यों में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या और डकैती एक ही लेन-देन के अभिन्न अंग साबित हुए हैं और इसलिए धारा 114 चित्रण (ए) के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा यह है कि अपीलकर्ता ने न केवल मृतक की हत्या की, बल्कि उसके आभूषणों की डकैती भी की।

19. वर्तमान मामले में भी, आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध के अगले दिन प्रकटीकरण बयान दिए गए थे और मृतक की संपत्ति उनके कहने पर उसी दिवस को उन स्थानों से बरामद की गई थी जहां उन्होंने ऐसी संपत्तियां रखी थीं। एक ही दिन। मुकुंद उर्फ कुंडू मिश्रा और अन्य, म.प्र. राज्य. एआईआर (1997) एससी 2622 और रोनी एलियास रोनाल्ड जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1998) एससी 1251

के मामलों में दिए गए निर्णय सभी प्रभाव रखते हैं। बाद वाले मामले में न्यायालय ने कहा:

"डकैती और मृतक (श्री मोहन ओहोल, श्रीमती रूनी ओहोल और श्री रोहन ओहोल) की हत्या के तुरंत बाद अपीलकर्ताओं के कब्जे से ओहोल परिवार से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी होना अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ए) के तहत अनुमान को आकर्षित करेंगे। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि हत्या और वस्तुओं की लूट एक ही लेनदेन का हिस्सा पाई गई थी, इसलिए निष्कर्ष यही होगा कि अपीलकर्ताओं के अलावा और किसी अन्य ने तीन हत्याएं और डकैती नहीं की थी।"

20. इन पहलुओं को संजय उर्फ काका बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) [2001] 3 एससीसी 190 के मामले में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था।

21. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, अपील स्पष्ट रूप से निराधार है और खारिज करने योग्य है, जिसको खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चेतली गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

\*\*\*